नईदुनिया

संपादकीय

रुक जाओ मम्मी-पापा, मोबाइल नहीं, आपका वक्त चाहिए

बाल दिवस पर सबसे कड़वा सच सामने आया, स्क्रीन ने निगल लिया बचपन। दो साल में ही ऑटिज्म जैसे लक्षण, तीन साल में अकेलापन। यह तरक्की है या तबाही? पेरेंट्स की सुविधा बनी बच्चों की सजा, अब नहीं चेते तो कल बहुत देर हो जाएगी। एक रिपोर्ट ने पूरे समाज को आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट बताती है कि मोबाइल की बढ़ती लत बच्चों के बचपन को निगल रही है। दो से तीन साल के बच्चों में भी चिड़चिड़ापन, तनाव और विकास संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कम उम्र में ही बच्चे अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह किसी एक शहर या मोहल्ले की कहानी नहीं, बल्कि हर घर की हकीकत बनती जा रही है। मां किचन में व्यस्त है, पिता लैपटॉप पर व्यस्त हैं और बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया गया है, ताकि वह रोए नहीं और माता-पिता अपने काम निपटा सकें। डॉक्टरों ने स्क्रीन के इस्तेमाल से जुड़े दस बड़े खतरे गिनाए हैं। बातचीत की कमी के कारण बच्चा बोलना सीखने की उम्र में भाषा और संवाद के विकास में पिछड़ सकता है। सामाजिक संपर्क घटने से बच्चों को दोस्तों के बजाय स्क्रीन का साथ ज्यादा अच्छा लगने लगता है। एकाग्रता में कमी के कारण स्कूल में बैठना और पढ़ाई पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। रात में मोबाइल की नीली रोशनी नींद की दुश्मन बनती है। मोबाइल देखते हुए खाना खाने से जंक फूड की आदत और मोटापे का खतरा बढ़ता है। आंखों पर जोर पड़ता है और कम उम्र में नजर कमजोर होने की समस्या सामने आती है। लगातार झुककर मोबाइल देखने से पीठ और गर्दन पर असर पड़ता है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हिंसक व्यवहार और अकेलेपन जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। बड़ों से बातचीत और मेलजोल कम होने से बच्चों के सामाजिक व्यवहार और संस्कारों पर भी असर पड़ता है।

ये सभी खतरे माता-पिता से सीधा सवाल करते हैं। आपने बच्चे को जन्म दिया है या मोबाइल को? आप कहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता, इसलिए मोबाइल दिखाते हैं। बच्चा जिद करता है, इसलिए मोबाइल दे देते हैं। सच यह है कि बच्चा जिद नहीं करता, आप उसकी जिद से बचना चाहते हैं। आपको लगता है कि मोबाइल देने से कुछ देर के लिए परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि धीरे-धीरे बच्चा आपसे दूर होता जा रहा है। आपने कभी देखा है कि दो साल के बच्चे से मोबाइल छीनने पर वह किस तरह चीखने लगता है? यह लत का संकेत है और इसकी आदत डालने में कहीं न कहीं हमारी भूमिका भी है। यदि अभी भी सुधार नहीं हुआ और माता-पिता गंभीर नहीं हुए, तो परिणाम और चिंताजनक हो सकते हैं। आज जो बच्चा छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो रहा है, वह आगे चलकर व्यवहार संबंधी समस्याओं से जूझ सकता है। आज जो बच्चा अकेले रहना पसंद कर रहा है, उसके सामाजिक और भावनात्मक विकास पर असर पड़ सकता है। सरकार, स्कूल और डॉक्टर अपनी जगह हैं, लेकिन असली सुधार घर से शुरू होगा। घर में मोबाइल के इस्तेमाल की स्पष्ट सीमा तय करें। खाने की मेज, पूजा स्थल और सोने के बिस्तर पर मोबाइल को जगह न दें। रोज कम से कम एक घंटा स्क्रीन से दूर रहकर बच्चे के साथ बातचीत करें, खेलें और उसे कहानी सुनाएं। बच्चे को बोर भी होने दें, हर वक्त उसका मनोरंजन करने की जरूरत नहीं है। बोरियत से ही कल्पनाशीलता और रचनात्मकता विकसित होती है। सबसे जरूरी है कि माता-पिता खुद भी आदर्श बनें। आप रातभर मोबाइल पर रील देखेंगे, तो बच्चे से किताब पढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? शाम को उसे पार्क ले जाएं, दोस्तों के साथ खेलने दें और खुले मैदान में दौड़ने दें। बाल दिवस पर हम बच्चों को गुब्बारे, ट्रॉफियां और भाषण देते हैं, लेकिन बच्चा हमसे कुछ और मांग रहा है। वह कह रहा है, पापा, ऑफिस से आने के बाद मोबाइल मत देखिए, मेरे साथ खेलिए। मम्मी, किचन से निकलकर मुझे कहानी सुनाइए। उसे महंगे खिलौने नहीं, आपका साथ चाहिए। उसे मोबाइल की चमक नहीं, आपके चेहरे की मुस्कान चाहिए। यदि आपने उसकी यह छोटी-सी पुकार नहीं सुनी, तो एक दिन यही बच्चा बड़ा होकर आपसे दूर हो सकता है और आप उसके साथ बिताए बचपन के उन पलों को तरसेंगे। मोबाइल ने बचपन छीना है, तो उसे लौटाना भी हमें ही होगा। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आपके घर के आंगन में बच्चों की हंसी की जगह मोबाइल की आवाजें ही रह जाएं।

आजकल

वर्दी के भीतर धड़कता है एक पिता का दिल

बर्फ में बंद रास्ते और खुले दिल वाले जवान 900 लोग नहीं, 900 परिवार बचाए त्रिशक्ति कोर ने जब पर्यटक सेल्फी भूलकर जवान के कंधे पर रोया

सेना की तस्वीर हमारे दिमाग में क्या है? सीमा पर खड़ा जवान, बर्फ में जमी राइफल और आंखों में गुस्सा। पर सिक्किम की बर्फ ने इस तस्वीर को बदल दिया। वहां राइफल नहीं, कंबल था। गुस्सा नहीं, गर्म चाय थी और दुश्मन नहीं, देश के अपने लोग थे, जो बर्फ में फंसे थे। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने नाथूला, बाबा धाम और त्सोमगो झील के आसपास जो किया, वह केवल बचाव अभियान नहीं, इंसानियत की मिसाल थी। एक अनजान पर्यटक और अनजान जवान के बीच ऐसा रिश्ता बना, जिसमें जवान ने बिना नाम पूछे मदद का हाथ बढ़ा दिया। गंगटोक से जेएन रोड तक सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंसी थीं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पर्यटक ठंड से परेशान थे। मोबाइल नेटवर्क बाधित था और बर्फ लगातार गिर रही थी। ऐसे में जवानों ने अपनी बैरक खोली, गर्म खाना बनाया, चाय पिलाई और लोगों को सुरक्षित आश्रय दिया। यह संवेदनशीलता केवल प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि संस्कारों और मानवीय भावनाओं से आती है। जवान जब किसी बच्चे को कांपते देखता है, तो उसे अपना परिवार याद आता है। यही भावना उसे सैनिक के साथ संवेदनशील इंसान भी बनाती है।

सेना ने लगभग 900 लोगों को बचाकर केवल जिंदगियां नहीं, सैकड़ों परिवारों की खुशियां और उम्मीदें भी बचाईं। त्रिशक्ति कोर ने साबित किया कि वह केवल सीमाओं की रखवाली नहीं करती, बल्कि संकट में देशवासियों की ढाल भी बनती है। इस घटना से पर्यटकों को भी सीख लेनी चाहिए कि मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें और पर्याप्त तैयारी के साथ यात्रा करें। भारतीय सेना की असली ताकत केवल मिसाइल और टैंक नहीं, बल्कि उसके जवानों का संवेदनशील हृदय भी है। सिक्किम के जवानों ने दिखाया कि वर्दी पहनने से दिल कठोर नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी और इंसानियत का दायरा और बड़ा हो जाता है।

गठबंधन एक, प्रभावित होंगे अनेक, नया समीकरण बदलेगा यूपी का गणित

ओवैसी और आजाद का हाथ मिलना, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का ऐलान। दलित-मुस्लिम गठजोड़ की पुरानी कोशिश, नई बोतल में पुरानी शराब। 403 सीटों पर लड़ने का दावा, किसका वोट कटेगा? कांग्रेस, सपा और बसपा की बेचैनी क्यों बढ़ी? भाजपा को फायदा या नुकसान, किसे मिलेगा लाभ?

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में नए गठबंधन की घोषणा हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन का ऐलान करते हुए इसे सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम दिया है। इस घोषणा के बाद प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य दलित और मुस्लिम वोटों को एक मंच पर लाना तथा युवाओं, किसानों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाना है। माना जा रहा है कि यह गठबंधन समाजवादी पार्टी के दलित-अल्पसंख्यक समीकरण के सामने नई चुनौती पेश कर सकता है।

यह गठबंधन सिर्फ दो नेताओं का मिलन नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं और दो वोट बैंक को एक साथ लाने की कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाताओं में है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रभाव दलितों, खासकर जाटव समाज और युवाओं में माना जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम करीब 20 प्रतिशत हैं। यदि दोनों वोट बैंक एक साथ आ जाएं, तो यह करीब 40 प्रतिशत का बड़ा सामाजिक आधार बन सकता है, जो किसी भी चुनाव के नतीजे पलटने की ताकत रखता है। इसी कारण दोनों नेताओं ने अपने मोर्चे के प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसका मतलब है कि वे किसी बड़ी पार्टी के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते, बल्कि तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन का असर केवल वोटों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक दलित और मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपना पारंपरिक आधार मानती रही हैं। सपा ने मुस्लिम-यादव गठजोड़ बनाया, तो बसपा ने दलित-ब्राह्मण और दलित-मुस्लिम गठजोड़ के प्रयोग किए। पर पिछले कुछ चुनावों में बसपा का जनाधार खिसका और सपा के मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगी। ऐसे में ओवैसी और आजाद ने इस खाली जगह को भरने की कोशिश की है।



अब सवाल है कि इस गठबंधन से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की। भाजपा को इस गठबंधन से सीधा फायदा मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब मुस्लिम वोट बंटता है, तो भाजपा को फायदा होता है। वर्ष 2017 और 2022 के चुनावों में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले, जब ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से सपा और बसपा के मुस्लिम उम्मीदवारों के वोट प्रभावित हुए और भाजपा कुछ सीटों पर कम अंतर से जीत गई। यदि इस बार ओवैसी और आजाद मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो मुस्लिम और दलित वोटों का बंटवारा हो सकता है और इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। भाजपा इसीलिए इस गठबंधन को लेकर बहुत आक्रामक नहीं दिख रही है, क्योंकि विरोधी वोटों का बंटना उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी बड़ी प्रभावित पार्टी समाजवादी पार्टी हो सकती है। सपा अपने को मुस्लिम और यादवों के साथ-साथ दलितों का भी हितैषी बताती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के आने से दलित युवाओं का एक वर्ग सपा से दूर हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी का अच्छा प्रभाव है और वहां जाटव समाज का एक वर्ग चंद्रशेखर को अपने नए नेता के रूप में देखता है। यदि जाटव वोट सपा से हटकर आजाद के साथ जाता है, तो सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगने की आशंका है। ओवैसी लगातार सपा पर आरोप लगाते रहे हैं कि उसने मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा और उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इस कारण कई मुस्लिम युवा ओवैसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बसपा के लिए यह गठबंधन सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। बसपा का कोर वोट बैंक जाटव समाज है और चंद्रशेखर आजाद भी इसी समाज से आते हैं। वे खुद को कांशीराम की विचारधारा का उत्तराधिकारी बताते हैं। मायावती की सीमित राजनीतिक सक्रियता के बीच दलित युवाओं में नए नेतृत्व की तलाश है और चंद्रशेखर उस आकांक्षा के विकल्प के रूप में उभरते दिख रहे हैं। यदि जाटव वोट बसपा से छिटककर आजाद समाज पार्टी के साथ जाता है, तो बसपा की राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत गिरकर करीब 12 प्रतिशत रह गया था। यदि इस बार इसमें और गिरावट आती है, तो पार्टी के सामने राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती खड़ी हो सकती है। चौथी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पहले से ही कमजोर है और वह दलित तथा मुस्लिम वोटों को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और संविधान बचाओ अभियान का असर दलित और मुस्लिम समाज के एक वर्ग में दिखाई दिया था, लेकिन ओवैसी और आजाद के गठबंधन ने कांग्रेस की इस कोशिश को झटका दिया है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दलित या मुस्लिम चेहरा नहीं है, जबकि इस मोर्चे के पास दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। इसलिए कांग्रेस को अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे दलों की बात करें, तो ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और संजय निषाद की निषाद पार्टी जैसे दल भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वे भी पिछड़े और दलित वोटों पर निर्भर हैं।

इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती इसका टिकाऊपन है। क्या यह गठबंधन 2027 तक टिका रहेगा? क्या सीटों के बंटवारे पर सहमति बन पाएगी? क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद नहीं होगा? इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सामाजिक मोर्चे बने और टूट गए। वर्ष 2022 में भी ओवैसी और राजभर ने गठबंधन किया था, लेकिन बाद में यह टूट गया। चंद्रशेखर आजाद ने भी पहले सपा के साथ जाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए इस नए मोर्चे को अपनी एकता साबित करनी होगी। इसके अलावा संगठनात्मक ढांचा भी बड़ी चुनौती है। क्या भीम आर्मी और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता गांव स्तर तक एक साथ काम कर पाएंगे? क्या बूथ स्तर पर तालमेल बैठ पाएगा? यह देखना होगा।

गठबंधन एक है, लेकिन प्रभावित अनेक होंगे। यह गठबंधन किसी को फायदा पहुंचा सकता है, तो किसी को नुकसान। भाजपा को लाभ हो सकता है, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच केंद्रित रहा है, लेकिन इस नए मोर्चे के आने से मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है। यदि यह मोर्चा 10 से 15 प्रतिशत वोट भी हासिल कर लेता है, तो कई सीटों पर हार-जीत का अंतर बदल सकता है। यही इस गठबंधन की असली ताकत होगी। अब देखना यह है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनता है या फिर केवल वोटों के बंटवारे तक सीमित रह जाता है। **(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)**

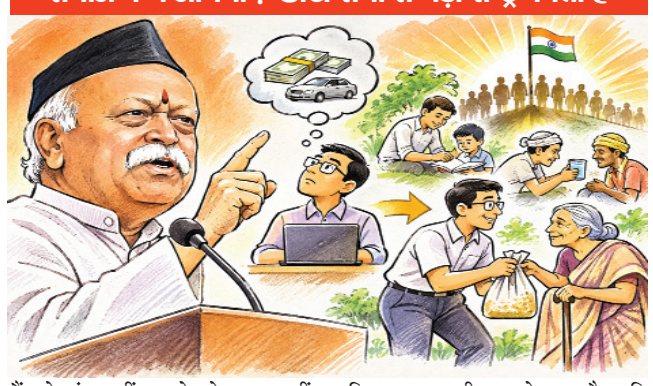
पेशा नहीं, संस्कार है सेवा

हम क्यों काम करते हैं, पेट के लिए नहीं, समाज के लिए पुरस्कार नहीं, प्रेरणा है विदर्भ गौरव का असली अर्थ

बिना अपेक्षा के मदद ही सच्ची मानवता है। पढ़ा-लिखा समाज कब जागेगा ? छोटी सेवा से बड़ा राष्ट्र बनता है

नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा, वह एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। उन्होंने कहा कि सेवा कोई पेशा नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आज के दौर में, जब हर रिश्ते को पैसे से तौला जा रहा है और हर मदद के पीछे स्वार्थ देखा जा रहा है, तब यह बात बहुत गंभीर और गहरी है। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि जीवन यही है। पर भागवत पूछते हैं कि क्या जीवन केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए है? क्या हम केवल अपने परिवार के लिए जीते हैं? यदि हां, तो फिर इंसान और मशीन में फर्क क्या रह गया? मशीन भी अपना काम करती है, पर इंसान का काम है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना। भागवत ने कहा कि हम केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए काम नहीं करते। यह वाक्य हर युवा को अपने दिल पर लिख लेना चाहिए। आज का युवा पूछता है कि इस काम से मुझे क्या मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, फायदा क्या होगा? पर कोई यह नहीं पूछता कि इस काम से समाज को क्या मिलेगा, मेरे गांव को क्या मिलेगा, मेरे देश को क्या मिलेगा? यही सोच देश को कमजोर करती है। जब तक हम केवल अपने लिए सोचेंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा और जब समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सेवा को पेशा मत बनाओ, उसे जिम्मेदारी बनाओ। जैसे पिता अपने बेटे की देखभाल को नौकरी नहीं समझता, वैसे ही समाज की देखभाल को भी नौकरी मत समझो।

पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इस पर भी भागवत ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि पुरस्कार इसलिए नहीं दिया जाता कि किसी ने कोई बड़ा चमत्कार कर दिया है। पुरस्कार इसलिए दिया जाता है, ताकि समाज को पता चले कि अच्छे लोग अभी भी जिंदा हैं और दूसरों को भी उनसे प्रेरणा मिले। विदर्भ गौरव पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर संजय जैसे लोग चुपचाप समाज की सेवा कर रहे हैं। वे मंच नहीं चाहते, वे माला नहीं चाहते, वे बस काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जब मंच पर बुलाया जाता है, तो समाज को एक संदेश जाता है कि देखो, यही असली हीरो हैं, यही असली सेलिब्रिटी हैं। आज जरूरत है कि हम फिल्मी हीरो की जगह ऐसे असली हीरो को सम्मान दें।



बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा ही समाज की बुनियाद है। लोगों को बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यह बात आज के मतलबी युग में एक दीपक की तरह है। हम मदद भी करते हैं, तो फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं, ताकि लोग हमें महान कहें। पर सच्ची सेवा वह है, जिसका कोई गवाह नहीं होता, कोई फोटो नहीं होती, कोई ताली नहीं बजती। बस एक व्यक्ति का दुख कम हो जाता है और मदद करने वाले को अंदर से शांति मिलती है। वही शांति असली पुरस्कार है।

बौद्धिक समाज के लिए यह सबसे गंभीर संदेश है। आज का पढ़ा-लिखा वर्ग समाज से कटता जा रहा है। वह अपने फ्लैट में बंद है, अपने लैपटॉप में व्यस्त है। उसे लगता है कि गरीब की मदद करना सरकार का काम है, गंदगी साफ करना नगर निगम का काम है और देश चलाना नेताओं का काम है। पर भागवत कहते हैं कि नहीं, यह सब हमारा काम है। यदि हम पढ़े-लिखे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। हमें समाज को दिशा देनी है, ज्ञान को किताबों से निकालकर गली तक ले जाना है। यदि बौद्धिक वर्ग ही समाज से मुंह मोड़ लेगा, तो समाज को रास्ता कौन दिखाएगा? इसलिए उठो, अपनी किताबों से बाहर आओ और देखो कि तुम्हारे आसपास कौन दुखी है।

छोटी सेवा से ही बड़ा राष्ट्र बनता है। किसी को लगता है कि सेवा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ा संगठन चाहिए, पर सच यह है कि सेवा एक छोटे कदम से शुरू होती है। एक बच्चे को एक घंटा पढ़ा देना सेवा है, एक प्यासे को पानी पिला देना सेवा है, एक अकेले बुजुर्ग के पास बैठकर उसकी बात सुन लेना सेवा है। यही छोटी-छोटी सेवाएं मिलकर बड़ा समाज बनाती हैं और बड़ा समाज मिलकर महान राष्ट्र बनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही मंत्र है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण सेवा से होता है। इसलिए हर दिन एक छोटी सेवा का संकल्प लो, बिना नाम के, बिना दाम के। यदि आज तुम नहीं रहे, तो समाज तुम्हें क्यों याद रखेगा? तुम्हारी सैलरी के लिए, तुम्हारी कार के लिए या तुम्हारी मदद के लिए? याद रखो, लोग तुम्हारे पद को नहीं, तुम्हारे व्यवहार को याद रखते हैं। सेवा कोई पेशा नहीं है, यह एक संस्कार है, जो तुम्हें अपने माता-पिता से मिलता है और जिसे तुम अपने बच्चों को देते हो। इसे बचाए रखो, क्योंकि जिस दिन समाज से सेवा खत्म हो गई, उस दिन समाज भी खत्म हो जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

भोपाल का मास्टर प्लान : विकास का नक्शा या भविष्य का संकट ?

चौदह हजार आवाजें पूछ रही हैं, मास्टर प्लान किसके लिए? अरेरा कॉलोनी से बैरसिया के खेतों तक एक ही चिंता। तालाब बचेंगे तो बचेगा भोपाल। सुनवाई रस्म है या समाधान? भोपाल का मास्टर प्लान 2047 आज फिर कठघरे में है और कठघरे में है भरोसा। चौदह हजार तीन सौ आपत्तियां केवल कागज नहीं हैं, ये चौदह हजार परिवारों की चिंताएं हैं। किसी की जमीन का सवाल है, किसी के घर का सवाल है और किसी के भविष्य का सवाल है। जब एक शहर के अगले बीस साल का नक्शा बनता है, तो उसमें उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन यहां नक्शे में ही डर दिखाई दे रहा है। अरेरा कॉलोनी के लोग डर रहे हैं कि उनकी शांत कॉलोनी बाजार में बदल जाएगी और 60 पंचायतों के किसान डर रहे हैं कि उनके खेत शहर में बदल जाएंगे। दोनों की चिंता एक ही है कि बिना पूछे हमारे बारे में फैसला क्यों लिया गया?

मास्टर प्लान बनाने वाले एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर नक्शा खींचते हैं और सोचते हैं कि जनता उसे मान लेगी, लेकिन भोपाल ने बता दिया है कि जनता इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। तीन हजार से ज्यादा आवेदन तो छंटनी में ही खारिज हो गए, जबकि बाकी दस हजार से ज्यादा आपत्तियां सुनवाई के लिए बची हैं। सबसे ज्यादा आपत्तियां जमीन के उपयोग यानी लैंड यूज को लेकर हैं। छह हजार से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि उनकी जमीन का उपयोग बदल दिया गया है। किसी की कृषि भूमि को आवासीय बना दिया गया, तो किसी की आवासीय भूमि को हरित क्षेत्र में डाल दिया गया। इससे जमीन की कीमत प्रभावित हुई और लोगों को अपने अधिकार छिनने का डर सता रहा है। यह केवल नक्शे की गलती नहीं, बल्कि लोगों के जीवन पर चोट है। भोपाल झीलों से है और झीलें पानी से हैं, लेकिन मास्टर प्लान में तालाबों के कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण की छूट की बात है। यह छूट नहीं, बल्कि भविष्य के लिए खतरा है। यदि कैचमेंट क्षेत्र में घर बनेंगे, तो पानी झीलों तक कैसे पहुंचेगा? भोपाल की पहचान बड़ा तालाब और छोटा तालाब हैं। यदि इनके जलग्रहण क्षेत्रों में ही निर्माण होने लगेगा, तो झीलों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। पहले ही कई छोटी झीलें अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी हैं। अब यदि बड़े तालाबों को भी नहीं बचाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। यह भोपाल का सबसे गंभीर संदेश है। मास्टर प्लान में 60 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। वहां के लोगों ने भी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका सवाल सीधा है कि हमें शहर नहीं बनना, हमें गांव ही रहने दो। शहर में शामिल होने से टैक्स और नियम बढ़ेंगे, लेकिन क्या उसी अनुपात में सुविधाएं भी बढ़ेंगी? ग्रामीणों को आशंका है कि उनकी जमीन का वास्तविक लाभ उन्हें नहीं मिलेगा और वह बिल्डरों के हाथों में चली जाएगी। यह डर निराधार नहीं है। मध्यप्रदेश में कई जगह ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहां गांवों को शहरों में शामिल करने के बाद किसानों की आजीविका और जमीन से जुड़े सवाल खड़े हुए। इसलिए ग्रामीणों की आपत्तियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उनकी जमीन उनका अधिकार है और उनके सम्मान से जुड़ा सवाल भी है। अब बात सुनवाई की है। 16 नवंबर से सुनवाई शुरू हो रही है। पहले दिन 1600 लोगों को बुलाया गया है और प्रतिदिन एक हजार आपत्तियों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। यह आंकड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सवाल है कि क्या एक दिन में एक हजार लोगों की बात वास्तव में सुनी जा सकती है? क्या एक हजार परिवारों की समस्याओं का समाधान सुबह से शाम तक सुनवाई करके हो जाएगा? प्रशासन ने कहा है कि एक जैसी आपत्तियों को सामूहिक रूप से सुना जाएगा। इससे समय जरूर बचेगा, लेकिन क्या न्याय भी मिल पाएगा? हर व्यक्ति की जमीन का मामला अलग है और हर परिवार की कहानी अलग है। सामूहिक सुनवाई में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कैसे होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बना यह मास्टर प्लान भी एक सच्चाई है। बीस साल से लंबित मास्टर प्लान तब जारी हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए और सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लगी। इसका मतलब है कि यह प्लान प्रशासनिक इच्छाशक्ति से पहले न्यायिक हस्तक्षेप के बाद आगे बढ़ा। 23 नवंबर को कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है, इसलिए प्रशासन जल्दी में है। लेकिन जल्दी में न्याय नहीं होता। भोपाल जैसे शहर का प्लान अगले बीस साल तक शहर की दिशा तय करेगा। ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर आपत्तियों का निपटारा जल्दबाजी में करना उचित नहीं है। यदि चौदह हजार लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, तो समझना होगा कि कहीं न कहीं भरोसे का संकट है। लोगों को लग रहा है कि यह प्लान जनता की जरूरतों से ज्यादा बिल्डरों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस भरोसे को वापस लाने के लिए सुनवाई को महज रस्म नहीं बनने देना होगा। सांसद, विधायक और अधिकारी यदि एक मंच पर बैठकर लोगों की आपत्तियां सुनेंगे, तो उन्हें समस्याओं को समझना भी होगा और उचित समाधान भी देना होगा। अन्यथा यह मास्टर प्लान कागजों में ही उलझा रहेगा और भोपाल बिना समुचित योजना के बेतरतीब ढंग से बढ़ता रहेगा। हमें ऐसा भोपाल नहीं चाहिए। हमें ऐसा भोपाल चाहिए, जहां झीलें भी बचें, खेत भी बचें और घर भी सुरक्षित रहें। यही विकास का वास्तविक मास्टर प्लान होगा। **(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)**

इकहत्तर अंकों वाला भारत दुनिया की उम्मीद क्यों बना

नंबर नहीं, नजरिया है एसोचैम की रिपोर्ट का असली संदेश। तेल की धार पर नहीं, भरोसे की धार पर टिका है विकास। जापान-जर्मनी पीछे छूटे, भारत आगे क्यों निकला? तीसरे पायदान की कीमत क्या है और किसे चुकानी है? 2030 तक यह बढ़त कैसे कायम रहेगी?

दुनिया जब डगमगा रही है, तब भारत क्यों स्थिर दिखाई दे रहा है? इसका जवाब एसोचैम की ताजा रिपोर्ट में छिपा है। उद्योग मंडल एसोचैम ने दुनिया की दस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को दस कसौटियों पर परखा और भारत को 100 में से 71 अंक देकर सबसे ऊपर रखा। चीन को 66 अंक मिले और वह दूसरे स्थान पर रहा। यह केवल अंक नहीं हैं, बल्कि एक सोच का परिणाम है कि भारत अब केवल बाजार नहीं, बल्कि भरोसेमंद भविष्य भी है। रिपोर्ट कहती है कि 2026 से 2030 तक भारत का यह दबदबा कायम रहेगा और वह सबसे तेज तथा संतुलित अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा।

अंक कैसे दिए गए, यह समझना जरूरी है। सरकार का कर्ज, प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक जीडीपी वृद्धि, निर्यात में बढ़ोतरी, राजकोषीय घाटा, चालू खाते का संतुलन, घरेलू बचत और पूंजी निर्माण जैसे दस पैमानों पर देशों को आंका गया। भारत ने इनमें से कई पर पहला या दूसरा स्थान पाया। निर्यात वृद्धि और कर्ज-जीडीपी के बेहतर प्रबंधन में भारत पहले स्थान पर रहा, जबकि बचत और निवेश में वह दूसरे स्थान पर रहा। इसका अर्थ है कि भारत केवल खर्च नहीं कर रहा, बल्कि बचत भी कर रहा है और भविष्य के लिए पूंजी भी बना रहा है। वहीं अमेरिका को 36 अंक, ब्रिटेन को 52 अंक और फ्रांस को 40 अंक मिले। यानी पुरानी महाशक्तियां नए भारत से पीछे छूट रही हैं।

तेल का खेल भी इस कहानी में अहम है। भारत ने अक्टूबर में रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा। एक महीने में 66,780 करोड़ रुपये का ईंधन खरीदा गया, जो 2022 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। कई लोग इसे कमजोरी समझेंगे कि हम अभी भी तेल के लिए विदेशों पर निर्भर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अपेक्षाकृत सस्ता तेल खरीदकर भारत ने अपनी महंगाई को काबू में रखने और अपनी फैक्ट्रियों को चलाए रखने में मदद हासिल की। जब यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, तब भारत के कारखाने चल रहे थे। यही आर्थिक समझदारी है। सस्ता तेल खरीदकर देश की उत्पादन लागत को कम रखना और अर्थव्यवस्था को गति देना भी विकास की रणनीति का हिस्सा है। इससे घरेलू बचत बढ़ी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही।



जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ने की कहानी केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि मानसिकता की भी है। जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है और घट रही है। जर्मनी ऊर्जा संकट और युद्ध के असर से जूझ रहा है। अमेरिका कर्ज में डूबा है, जबकि भारत युवा है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। जब युवा काम करता है, तो देश आगे बढ़ता है। स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, डिजिटल लेनदेन में भारत दुनिया में अग्रणी है, सड़कें बन रही हैं, बंदरगाहों की क्षमता बढ़ रही है और गांवों तक इंटरनेट पहुंच रहा है। यही बुनियादी ताकत भारत को 71 अंक दिलाती है। अब सव